माईगव हिमाचल न्यूजलेटर

डिजिटल मासिक पत्रिका

शिमला (हिमाचल प्रदेश)| वर्ष: 01 | अंक: 04 | मार्च 2021 himachal.mygov.in

Visit & Participate himachal.mygov.in /mygovhimachal

हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया 50,192 करोड़ का बजट

8 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित बजट में शामिल की हैं 12 नई जनकल्याणकारी योजनाएं, कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है इस वित्तीय वर्ष का बजट

माईगव, हिमाचल|

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कोरोना महामारी के बावजूद पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। सरकार ने इस बजट में 12 नई योजनाओं को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त यह बजट में 8 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है, उन बिंदुओं में महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता शामिल है। निश्चित तौर पर इन बिंदुओं के आधार पर राज्य के सभी वर्ग एवं क्षेत्रों का समग्र विकास हो सकेगा।

12 नई जनकल्याणकारी योजनाएं होंगी शुरू -

- स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प योजना (संपर्क)
- स्वर्ण जयंती जिला नवाचार निधि
- स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना (बीज संरक्षण)
- स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना (समृद्ध बागवान)
- स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह योजना (सहयोग)
- बैंक पत्राचार सखी (सखी)
- स्वर्णिम वाटिका
- हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल (हिम शिक्षा)
- स्वर्ण जयंती हरित भवन पहल
- शगुन
- स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना (नारी सम्बल)
- नशा सेवन निवारण निधि

सामाजिक सुरक्षा में किया अभूतपूर्व विस्तार

माईगव, हिमाचल|

हिमाचल सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकार ने फैसला किया है कि आगामी वर्ष 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार इस पर 60 करोड़ रुपये व्यय करेगी। बता दें कि वर्तमान हिमाचल सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 लाख 60 हजार लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाए गए हैं जिस पर 1,050 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना अनुसूचित जाति कल्याण

माईगव, हिमाचल|

हिमाचल सरकार ने स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के अन्तर्गत 12 हजार लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु हिमाचल सरकार प्रभावी कदम उठाएगी।

महिलाओं का बढ़ाया सम्मान, बजट में किया करोड़ों का प्रावधान

माईगव, हिमाचल|

हिमाचल सरकार ने बजट 2021-22 में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के दृष्टिगत विशेष प्रावधान किया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना के अंतर्गत 65-69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिस पर 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी।

शगुन नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, जनरल तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

वहीं बीपीएल परिवारों को दो लड़कियों तक अब 21 हज़ार रुपये की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए पहल की जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफिल अगले वर्ष भी दिया जाएगा। राज्य में 136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे। पुलिस में आरक्षी एवं उप-निरीक्षक के लिए चरणबद्ध समय में 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 250 महिलाओं को बैंक कोरेस्पोंडेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

आमजन के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, सेवाओं का किया विस्तार

हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 3,016 करोड़ रुपए का प्रावधान

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है कि आईजीएमसी में पीईटी स्कैन की सुविधा, टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन तथा एमआरआई मशीनें तथा हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। इनके लिए 70 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। शिमला स्थित चमयाना के सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल, आईजीएमसी के ओपीडी ब्लॉक तथा ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के हिमकेयर लाभार्थियों तथा बाल आश्रमों में रह रहे बच्चों को हिमकेयर में अंशदान से छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं कक्षा छठी से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच एवं निशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए मिशन दृष्टि आरंभ किया जाएगा। कुपोषण की समस्या के निदान के लिये नीति आयोग, केंद्र सरकार की भागीदारी से अध्ययन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, हिमकेयर,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, निशुल्क दवाइयां, सहारा योजना, सम्मान योजना, निक्षय पोषण सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार 2021-22 में 250 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेगी। हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 3,016 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सुदृढ़ होगी कृषि-बागवानी, आय होगी दोगुनी

माईगव, हिमाचल।

किसानों व बागवानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी ध्येय के साथ सरकार उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान योजना शुरू करेगी। कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना में बजट की बढ़ौतरी की जाएगी। हिमाचल सरकार इस पर 60 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत पांच लाख पौधों का आयात, 8 हज़ार हैक्टेयर कमांड एरिया के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में जीन रिपोजिटरी की स्थापना और पराला शिमला स्थित संयंत्र में एप्पल जूस कंसन्ट्रेट प्लांट की स्थापना होगी। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत 50 हजार नए किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में योजनाओं को पुनर्भाशित करने तथा किसानों व बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप भी गठित किया जाएगा।

गुणवत्ता शिक्षा पर दिया बल विद्यार्थियों का बढ़ेगा मनोबल

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल सरकार ने वित्तीय बजट 2021-22 में शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करेगा। इसके साथ ही सरकार टॉप 100 छात्रवृति योजना भी शुरू करेगी। 100 स्कूलों में मैथ लैब की स्थापना की जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग एवं कैरियर कांउसलिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट योजना के अन्तर्गत क्रमशः 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा विभाग के 400 करोड़ रुपये के 8 संस्थान जनता को समर्पित किए जाएंगे जो ज्यूरी, सुन्दरनगर, कुमारसेन, अर्की, गंगथ, करसोग, रैहन, बंदला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आईटी और एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में बढ़ौतरी और स्कूल टूर्नामेंट के प्रतिभागियों की डाइट मनी दोगुनी की गई है।

शहरी क्षेत्रों को करोड़ों की लागत से संवारेगी हिमाचल सरकार

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल सरकार ने वित्तीय बजट 2021-22 में राज्य के शहरी क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से संवारने के लिए करोड़ों का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा नवगठित शहरी निकायों व नए शामिल क्षेत्रों में हिमाचल सरकार ने तीन वर्षों के लिए सम्पत्ति करों में छूट दी गई है। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सड़कें, पार्किंग, ओपन जिम इत्यादि स्थापित किए जाएंगे। नवगठित शहरी निकायों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पद शीघ्र भरे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा नवगठित नगर पंचायत को 20 लाख रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार शिमला जल प्रबंधन निगम के माध्यम से लगभग 94 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण होने वाले विकास कार्यों को आगामी वर्ष जनता को समर्पित करेगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला शहर में वर्ष 2021-22 में 25 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी।

औद्योगिक विकास को मिलेगी मजबूती रोजगार के मिलेंगे नए अवसर

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल सरकार ने वित्तीय बजट 2021-22 में औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अटल सुरंग पर (दोनों ओर) पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग वे-साइड एमेनिटीज की स्थापना की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिये 5,000 पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर रखे जाएंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए उद्देश्य से सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सरकार 10,000 करोड़ रुपये के एमओयू की नई ग्राऊंड ब्रेकिंग की तैयारी कर रही है। ऊना जिला में ड्रग पार्क की स्थापना, नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क और नालागढ़ में इलैक्ट्रोनिक्स और पॉवर इक्युपमेंट हब का निर्माण प्रस्तावित है। सरकार द्वारा राज्य में खिलौना क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,125 किलो मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन तथा 140 किलोमीटर सड़कों पर डब्ल्यू-मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्लैक टॉप सड़कें जो अभी 30,244 किलोमीटर लम्बी हैं, 2022 तक 34,000 किलोमीटर कर दी जाएगी। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में दो हजार किलोमीटर मैटलिंग एंड टारिंग, 1 हजार किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 80 पुलों का निर्माण, 90 गांवों को सड़क सुविधा, 800 किलोमीटर सड़कों का

उन्नयन तथा 2 हजार 200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक योजनाएं शुरू और जनता को समर्पित की जाएंगी। नवगठित सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को एक-एक करोड़ रुपये तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपये विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक मल निकासी योजनाओं पर तीव्रता से काम किया जाएगा। स्वर्ण जयन्ती ऊर्जा नीति लाई जाएगी और पॉवर विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए मल्टी मीडिया पब्लीसिटी कैंपेन शुरू किया जाएगा। पर्यटन उद्योग की अनेक योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। 218 करोड़ रुपये की 19 योजनायें मनाली, जंजैहली, मण्डी, धर्मशाला, क्यारीघाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, शिमला, भलेई माता चम्बा, बीड़ बिलिंग, हाटकोटी, कांगनीधार, रामपुर और बद्दी में, 2021-22 में, जनता को समर्पित की जाएंगी। वहीं जल जीवन मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए तीन और जिलों सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में शत प्रतिशत पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा, कुल्लू व शिमला हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। 2021-22 में 1,016 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ मानदंडों पर सुदृढ़ किया जाएगा। कूड़े की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 नई बसें खरीदी जाएंगी और रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।

कर्मचारियों के मानदेय में होगी वृद्धि

माईगव, हिमाचल।

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के पार्टटाईम वाटर कैरियर और मिड-डे मील वर्कर, राजस्व विभाग के अंशकालिक वर्कर और नंबरदार, जल गार्ड, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए नए कॉलेज, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी कॉलेज, विकास खंड, तहसील, उपतहसील, पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, अग्निशन केंद्र इत्यादि खोले जाएंगे। जहां संभव होगा मौजूदा संसाधनों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्ययों को भी दोगुना किया जा रहा है।

न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई और अंशकालीन कर्मी और आऊटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी के साथ सरकार आऊटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के लिये भी प्रभावी कदम पग उठाएगी।

हिमाचल के युवा नहीं रहेंगे बेरोजगार, सरकार ने खोले रोजगार के द्वार

वर्ष 2021-22 में 30,000 से अधिक पद भरेगी राज्य सरकार

माईगव, हिमाचल।

प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। इसी दृष्टि से सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का विस्तार और बजट में बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस वर्ष रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों को और सहायता दी जाएगी। विशेष यह है कि हिमाचल सरकार ने वर्ष 2021-22 में 30,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000 पद और शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज के पद भरे जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग में 5,000 मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज और जल शक्ति विभाग में 4,000 पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्ज के पद भरे जाएंगे। कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना-2018 के अंतर्गत अब ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। हिमाचल सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त फंक्शनल पदों को भी भरेगी। इनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, एचआरटीसी में चालक एवं परिचालक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता के पद भरे जाएंगे।

राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, जेओए (आईटी) के पद और तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि के पद भरे जाएंगे।

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोग्रेमेटिक इंटरवेंशन्स में हिमाचल प्रदेश को मिला देश में पहला पुरस्कार

माईगव, हिमाचल।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप (प्रोग्रेमेटिक इंटरवेंशन्स) की रैंकिंग की है जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके अंतर्गत फरवरी, 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों ने आवेदन किए थे। इसका परिणाम हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए जिला लाहौल-स्पीति को क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए रजत पदक जबकि जिला किन्नौर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार वर्ष 2030 तक क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश ने ''मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना'' भी शुरू की है। इस वर्ष दि क्लॉक इज टिकिंग विषय पर राज्य स्तरीय क्षय उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया। वर्धन जी और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की दिशा में किए कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्वनी चैबे जी ने गए प्रयासों के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रदान हिमाचल प्रदेश के एनएचएम मिशन निदेशक किए गए पुरस्कार, प्रमाण-पत्र और स्मृति चिन्ह डॉ. निपुण जिंदल और एसटीओ डॉ. गोपाल को मुख्य सचिव श्री अनिल खाची और स्वास्थ्य बेरी को भेंट किए।

सचिव श्री अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भेंट किया।

हिमाचल प्रदेश 50 लाख से अधिक आबादी वालने राज्यों की श्रेणी में तपेदिक रोग समाप्त करने के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। यह पुरस्कार हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में तपेदिक का उन्मूलन उनके अथक प्रयासों और समर्पित सेवाओं के कारण ही संभव हो पाया है।

पीयूष ने राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में जीता कांस्य पदक

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इंदौर में हुई राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिमला के व्हीलचेयर यूजर खिलाड़ी पीयूष शर्मा को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। पीयूष शर्मा व्हील चेयर पर टेबल टेनिस खेलने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं। एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद आजकल गुरुग्राम में फेलोशिप पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की पीयूष शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य दिव्यांग छात्र-छात्राएं भी पीयूष शर्मा से प्रेरणा ले सकते हैं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने हमीरपुर के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और नीदरलैंड्स में पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल

बीज स्त्रोत और गुणन को लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के नामी बीज विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और किसानों ने दिए बहुमुल्य सुझाव

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल प्रदेश में बीज उत्पादन और इसकी उपलब्धता को लेकर शिमला में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की ओर से शिमला में आयोजित कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केवल 1 प्रतिशत भूमि में बीज का उत्पादन किया जा रहा है जो प्रदेश की 20 फीसदी बीज की जरूरत को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल 80 फीसदी से बीज दूसरे राज्यों से आयातित कर रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में देशभर से जुटे बीज विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और किसानों की मदद से हिमाचल में ही सभी प्रकार के उन्नत बीजों के उत्पादन और उनकी उपलब्धता को लेकर एक प्रणाली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अनूठी पहल की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल के पुराने बीजों को सहेजने और उनके गुणन के लिए भी प्रणाली को विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भले ही हमारा छोटा सा पहाड़ी राज्य पंजाब और हरियाणा के मुकाबले में अधिक पैदावार नहीं दे सकता है, लेकिन हम उच्च गुणवत्तापूर्वक बीज पैदा कर प्रदेश की जरूरत को पूरा करने के साथ अन्य राज्यों में उत्तम बीज निर्यात कर बीज राज्य के रूप में पहचान बना सकता है।

कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक और विशेष सचिव, राकेश कंवर ने कहा बाहरी राज्यों से आने वाले बीजों की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं।

कई बार बाहरी राज्यों से आने वाले बीजों का हिमाचल की पारिस्थितिकी के अनुसार न होने के चलते उनमें सही से अंकुरण नहीं होता है। इसलिए भी अब यह जरूरी बनता है कि हम हिमाचल प्रदेश की पारिस्थितिकी के अनुसार बीजों को तैयार करें और इसे प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत हिमाचल में ही बीज की उपलब्धता को लेकर एक शुरूआत की जा रही है।

इसके लिए पायलट आधार पर कृषि विभाग के 12 कृषि फार्मों और 130 किसान समूहों में उन्नत बीजों के उत्पादन का काम किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय पौध अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) और हिमाचल के उन्नत बीजों का संरक्षण करने वाले किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा।

इस मौके पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक प्रो राजेश्वर सिंह चंदेल ने बताया कि बीजों को लेकर इस राष्ट्रीय कार्यशाला में नामी विशेषज्ञों के बहुमुल्य सुझाव मिले हैं, जिन्हें हिमाचल में बीजों के उत्पादन और विपणन की रणनीति को तैयार करती बार प्रयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन को लाभ का काम बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादित बीजों के प्रमाणीकरण की प्रणाली भी तैयार की जाएगी।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में उत्तरा सिसोर्स डेवल्पमेंट सोसायटी उतराखंड के अध्यक्ष डॉ. विनोद भट्ट, उड़िसा लैंडरेसिज सीड वर्किंग ग्रुप की संयोजक भाग्य लक्ष्मी, पभोई ग्रीन्स असम के संस्थापक नीलम दत्ता, तमिलनाडु से हिमाकिरण अंगुला, महाराष्ट्र से सुजित चक्रवर्ती, तेलंगाना से शिव प्रसाद राजू और आरआरए नेटवर्क हैदराबाद से एन उदय कुमार मौजूद रहे।

इसके अलावा कृषि निदेशक हिमाचल एन के बधान, एनबीपीजीआर केंद्र शिमला प्रमुख डॉ. मोहर सिंह ठाकुर, सांइटिस्ट डॉ. जीडी शर्मा, डॉ. गोपाल कतना, डॉ. सुखदेव पालयाल, डॉ. एस सी वर्मा, डॉ. कुलदीप सिंह ठाकुर, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के निदेशक डॉ. युद्धवीर सिंह पठानिया और चौपाल के किसान मनोज शर्मा, करसोग से नेकराम शर्मा, सिरमौर से कुंदन शास्त्री, मंडी से संदीप कुमार, दिनेश कुमार और सोलन से गुरदेई देवी एवं रीना मौजूद रहीं।

इसके अलावा इस मौके पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयलसीड रिसर्च के पूर्व निदेशक डॉ. के वाराप्रसाद, इटली से रिकार्डो बोक्को और बोन जर्मनी से आइफोम के एकेडमी मैनेजर आशीष गुप्ता ऑनलाइन माध्यम से इस दो दिवसीय कार्यशाला में मौजूद रहे।